पीएम मोदी का जन्मदिन बना 'जुमला दिवस', रोजगार की माँग बुलंद

बेरोज़गारों का फूटा गुस्सा, जगह-जगह लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ!

नई दिल्ली (म.मो.) 17 सितम्बर विशेष दिन बन गया, जब प्रधानमंत्री मोदी के 70वें जन्मदिन को देश के युवाओं ने 'राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस' व 'जुलमा दिवस' के रूप में मनाया। दिनभर सोशल मीडिया पर

#NationalUnemploymentDay,

राष्ट्रीय बेरोज़गार दिवस,और जुमला दिवस टॉप पर ट्रेंड करते रहे। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस ने छात्रों पर लाठी चार्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया।

दमन के बीच जबर्दस्त विरोध प्रदर्शन

'युवा हल्ला बोल' आंदोलन की अपील पर इस दिन को युवाओं ने 'जुमला दिवस' की तरह मनाया तो कई अन्य युवा संगठनों और राजनीतिक दलों ने 'बेरोज़गारी दिवस' का आह्वाहन भी किया था। इसी के तहत राजधानी दिल्ली से लेकर देश के ज्यादातर राज्यों में बेरोजगारों का प्रदर्शन दिनभर जारी रहा। देश भर में छात्र-युवा सड़कों पर उतरे, कई जगहों पर मशाल जुलूस निकाले गए।

जुमला दिवस और बेरोज़गारी दिवस के रूप में मना पीएम मोदी का जन्मदिन, युवा बोले-जल्द दें रोजगार नहीं तो हर वर्ष मनाएंगे।

इलाहबाद में कई जगहों पर छात्र-युवा सड़कों पर उतर आए। जहाँ उनकी पुलिस से जमकर भिड़ंत हुई। बालसन चौराहे पर युवा मंच के बैनर तले हजारों छात्र-युवाओं ने भर्ती में संविदा प्रथा खत्म करने, खाली पदों को भरने, रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने, निजीकरण पर रोक लगाने जैसे सवालों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह समेत ग्यारह युवाओं को गिरफ्तार कर लिया।

पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में बीएचयू के छात्रों ने एक बड़ा मशाल जुलूस निकालकर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाया। इस दौरान छात्रों ने अपनी डिग्रियों की प्रतियां भी जलाईं।

बेरोजगारी को लेकर डिग्रियों की प्रति जलाकर यूथ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन

लखनऊ में प्रदर्शन के बीच यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओमवीर समेत 18 नेताओं को योगी सरकार ने जेल भेज दिया है। वहीं अलीगढ़ में बेरोजगार दिवस पर प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को योगी सरकार ने जेल भेज दिया है।

बिहार के कई जिलों में छात्र-युवा सड़कों पर उतरे। मोदी और नीतीश सरकार की रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ छात्र-युवाओं ने मशाल जुलूस निकाल पर अपना विरोध दर्ज कराया।

झारखंड में भी युवाओं ने मशाल जुलूस निकाल पर अपने गुस्से को प्रगट किया। जयपुर में सामूहिक रूप से युवाओं ने फाँसी लगाकर सांकेतिक प्रदर्शन किया।

उत्तराखंड में कई जिलों में प्रदर्शन हुए, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमांचल, गुजरात आदि राज्यों से भी जगह-जगह प्रदर्शन कर युवाओं ने गुस्से का इजहार किया। भोपाल में भी 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए।

सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड

जहाँ एक तरफ देश के कई शहरों में युवा आबादी सड़क पर उतर कर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मनाते हुए बेरोज़गारी के खिलाफ़ विरोध-प्रदर्शन करती रही। वहीं सोशल मीडिया पर भी आन्दोलन विकराल

रूप ले लिया। फेसबुक से लेकर यूट्यूब तक विरोध के विभिन्न रूप दिखे, वहीँ ट्विटर पर #national Unemploy Day, #बेरोज़गार दिवस, और राष्ट्रीय जुमला दिवस टॉप ट्रेंड करता रहा।

गिरफ़्तारी की निंदा, रिहाई की माँग

देशभर के विभिन्न जनवादी, युवा, छात्र संगठनों और राजनैतिक पार्टियों ने मोदी-योगी सरकार द्वारा युवाओं पर हुए लाठीचार्ज व गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि मोदी-योगी सरकार को युवाओं पर दमन ढहाने की जगह रोजगार के सवाल को हल करना चाहिए।

नेताओं ने सरकार से बिना शर्त युवाओं की अविलंब रिहाई की माँग करते हुए कहा कि देशी-विदेशी पूँजी की सेवा में लगी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। आपदा को मुनाफे के अवसर में बदल दिया है। रोजगार की जगह छंटनी तेज हुआ है, स्थाई की जगह संविदा और फिक्स टर्म का धंधा बढ़ गया है। बेरोजगारी भयावह रूप ले चुकी है। आन्दोलनकारियों ने कहा कि यदि सरकार ने रोजगार के सवाल को हल नहीं किया तो यह उसके लिए घातक साबित होगा।

सरकारी नौकरी में संविदा पर रखने के प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाये।

माध्यमिक, उच्चतर, प्राथमिक, पुलिस समेत प्रदेश में सभी विभागों में खाली पदों का विज्ञापन जारी किया जाए।

सभी लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा किया जाये।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेशित 8300/ 2018 तदर्थ शिक्षकों के पदों का अधियाचन मँगा कर विज्ञापन जारी किया जाए साथ ही साथ निश्चित समय सीमा में भर्ती पूरी की जाए । रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को प्रेषित करे।

श्रम

ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत होता तो रेलवे न बिकता, बैंक न लुटते

सतीश कुमार

जुझारू नेतृत्व में कर्मठ मज़दूरों ने जहां ट्रेड यूनियन आन्दोलन को मजबूत करते हुए न केवल देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया बल्कि इसकी रक्षा भी की। लेकिन जब नेतृत्व पथभ्रष्ट होने लगा तो न यूनियन रही न देश की अर्थव्यवस्था बची।

शुरू में कोई भी ट्रेड युनियनिस्ट भ्रष्ट नहीं होता और जो कोई होता भी है वह अपनी असलियत को ढक कर तीखे जुझारू तेवर दिखाता है। मजबूती से जड़ पकड़ने के बाद वह अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। यदि मज़दूर स्वयं जागरूक एवं सचेत हों राजनीतिक सिद्धांतों का ज्ञान रखते हों तो वे अपने नेता के पहले भटकते कदम को रोक सकते हैं। लेकिन यहां होती है अंध-भक्तों की भेड़चाल जो नेता के भटकने या बिकने के बाद पूरे आन्दोलन को ही अंधे कुएं में धकेल देती है।

इसे समझने के लिये बेहतरीन उदाहरण जॉर्ज फ़र्नांडिस का है। भारतीय रेलवे की जितनी बड़ी व मजबूत यूनियन उन्होंने खड़ी की, उसके उदाहरण विरले ही मिलते हैं। सन् 1973 में बतौर ताकतवर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी से टक्कर लेते हुए जितनी कामयाब रेलवे हड़ताल उन्होंने कराई थी, उसका उदाहरण ढूंढ पाना आसान नहीं। करीब एक सप्ताह भरके लिये पूरा देश खड़ा कर दिया था। सरकार झुकी रेलवे कर्मचारियों की तमाम जायज बातें मानी गयीं जिससे कर्मचारियों को तो लाभ हुआ ही रेलवे ने भी खासी उन्नति की। उन्होंने रेलवे के अलावा बोंबे टैक्सीमैन यूनियन भी देश की एक बड़ी ट्रेड यूनियन खड़ी की थी जिसके अपने पेट्रोल पम्प तक होते थे। लेकिन आज वह शिवसेना के अधीन है।

फ़िर से वापस आते हैं रेलवे पर। ऐसा नहीं है कि उस वक्त पूरे रेलवे में अकेले जार्ज की ही यूनियन थी, उस वक्त भी सीटू, एटक इन्टक एचएमएस, बीएमएस आदि का नेतृत्व चलता था। इस सब के बावजूद यह फ़र्नांडिस का ही करिश्मा था जो सबके सिर एक साथ जोड़ कर इन्दिरा जैसी तानाशाही शक्ति को सफल चुनौती दे

नेता और मज़दूर केवल अपने हितों तक ही सीमित हो कर रहे , उन्होंने अपनी राजनीतिक समझ विकसित नहीं की

डाली। इसी के फ़लस्वरूप इमरजेंसी में, मौका मिलते ही उन्होंने जॉर्ज को डायनामाइट के एक झूठे मुकदमें में लपेट कर फ़ांसी चढाने तक का षड्यंत्र रच डाला था। वक्त का पहिया घूमा इन्दिरा सत्ता से बाहर और जार्ज ने जेल से ही चुनाव जीत कर सत्ता में हिस्सेदारी पाई और हिस्सेदारी भी ऐसी पाई कि समाजवादी से संघवादी हो गये। लेकिन इस दौरान उन जुझारू मज़दूरों के संगठन डूबते चले गये जिनके दम पर जॉर्ज सत्ता की सीढियां चढते जा रहे थे। नेता और मज़दूर केवल अपने हितों तक ही सीमित हो कर रह गये। न तो उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझ को विकसित किया और न ही अपने संस्थान (रेलवे) के भविष्य की ओर ध्यान दिया। रेलवे की सेवा लेने वाले हर उपभोक्ता का भ्रष्टाचार एवं निकम्मेपन से सामना होने लगा। बेशक इसमें अधिक दोष सरकार एवं उसके आला अधिकारियों का रहा लेकिन यूनियन के माध्यम से उसका सशक्त विरोध करने की बजाय वे खुद भी इसमें भागीदारी करने लगे। सरकार भी यही चाहती थी, क्योंकि भ्रष्ट संगठन सरकार के सामने तन कर खड़े नहीं हो सकते। इसी का फ़ायदा उठाते हुए बीते आठ-दस साल से रेलवे में रिक्त पदों की संख्या 2 से 3, तीन से चार लाख तक होती चली गयी और यूनियनें मुंह ढक कर सोती रही। अब जब स्थिति रेलवे को बेचने तक कि आ गयी तो यूनियनों ने थोड़ी अंगड़ाई लेनी शुरू की है लेकिन अब इनकी वुक्कत कुछ खास रह नहीं गई; सरकार उनकी रत्ती भर परवाह नहीं करती। इसके लिये यूनियनें खुद जिम्मेवार हैं। आज यदि यूनियन मजबूत होती तो रेलवे की ऐसी दुर्दशा न होती।

बैंकों व जीवन बीमा निगम की यूनियनें भी रेलवे वालों से किसी तरह कम नहीं थी। वामपंथी विचारधारा से लैस एआईबीईए (अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन) का देश की बैंकिंग प्रणाली पर पूरा नियंत्रण था। इसका जन्म उस समय में हुआ था जब बैंक कर्मचारियों की हालत किसी लाला के मुनीम जैसी होती थी। नौकरी पर आने का समय तो निश्चित होता था लेकिन जाने का कोई समय नहीं होता था। देर रात को भी जाने से पहले पूछना पड़ता था कि ''मैं जाऊं रात बहुत हो गयी है?'' यदि मालिक/ मैनेजर का मूड सही हुआ तो कह देता था जाओ वरना कहता कि यह जो काम पड़ा है तेरा बाप करेगा?

ऐसी भयंकर गुलामी के हालात में अप्रैल 1946 में एचएल परवाना व डीपी चड्डा आदि ने इस गुलामी से मुक्ति दिलाने का बीड़ा उठाया था। विस्तृत विवरण की जरूरत नहीं , उस गुलामी से मुक्ति पाने के लिये बैंककर्मियों ने न केवल अपनी नौकरी बल्कि जान तक की बाज़ी लगा दी थी, तब कहीं जाकर काम करने के घंटे तय हुए, अधिक घंटे लगाने पर डबल ओवरटाइम के अलावा बेहतर सेवा शर्तों के साथ अच्छे वेतन भत्तों की शुरूआत हुई। यह सब बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले ही हो गया था। बैंकों में मजबूत ट्रेड यूनियन बनने से किसी भी बैंक के मुनाफ़े में कोई कमी नहीं आई बल्कि उसमें बढ़ोत्तरी होने लगी, क्योंकि तमाम कर्मचारी बेहतर एवं लाभकारी सेवा शर्तों से संतुष्ट होकर काम में मन लगा रहे थे। समय-समय पर जब भी कभी बैंक मालिकान ने कोई कर्मचारी विरोधी काम करना चाहा तो यूनियन ने अपनी शक्ति का खुल कर प्रदर्शन किया।

राष्ट्रीयकरण होने पर तमाम यूनियनों ने समर्थन किया व खुशी जताई। परन्तु सरकार ने अपने राजनीतिक हितों को साधने हेतु बैंकों की पूंजी लुटानी शुरू की तो यूनियन ने इस ओर उचित ध्यान नहीं दिया क्योंकि अब धीरे-धीरे यूनियन नेतृत्व पथ भ्रष्ट होने लगा था। जहां राजनेता अपने चहेतों में बैंक का धन बांटने में जुटे थे वही यूनियन नेता भी अपनी-औकात के अनुसार सेंधमारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। चंदे से मिलने वाले अपार धन ने यूनियन नेताओं की कार्यशैली अफ़सरशाही सरीखी बना दी। संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गयी।

इसका फ़ायदा उठाते हुए सरकारी प्रबन्धन ने खुल कर बैंक को लुटवाया, कर्मचारियों की संख्या घटा कर कार्यभार बढाया, आर्थिक हितों पर कुठाराघात किया। इतना ही नहीं बैंक ग्राहकों से भी वसूली के नये-नये तरीके खोज निकाले। इस सब के बावजूद आज न तो कर्मचारी कुछ बोलने की स्थिति में हैं और ग्राहक तो बोलेंगे ही क्या। स्थिति तो यहां तक बिगड़ चुकी है कि ग्राहकों का विश्वास ही बैंकों से उठता जा रहा है, वे सोच रहे हैं कि अपना पैसा बैंक में रखें या नहीं।

यदि बैंक कर्मचारियों की यूनियन पहले की तरह मजबूत एवं जुझारू रही होती तो आज बैंकों की यह दुर्दशा न हुई होती। बैंकों के 'मरजर' व निजीकरण की ओर वापसी न होती। इसी तरह यदि एलआईसी की यूनियन भी मजबूत बनी रहती तो आज इसके बिकने की नौबत न आती। (पाठकों की ओर से टिप्पणियां व आलोचनायें आमंत्रित हैं।)

(संपादक, मजदूर मोर्चा)

संपादक के नाम पत्र...

कॉमरेड, ट्रेड यूनियन की विश्वनीयता सन्देह के घेरे में बताते हुए आपने तथाकथित राष्ट्रीय संगठनों की एव तथाकथित मजदूर नेताओं के यथार्थ को खोल कर रख दिया। सहज और सरल भाषा में कमाल का जानकारीपूर्ण संस्मरण लेख बन गया है। श्रृंखला जारी रहे। नए मजदूर नेता व भावी पीढ़ी अवश्य प्रेरित व लाभान्वित होगी। पचास वर्षों के सार्थक प्रयासों, अनुभवों, घटनाओं एवं संस्मरणों की श्रृंखला अनवरत प्रकाशित हो। बाद में इन्हीं संस्मरणों का एकाकार पुस्तक रूप में आ जाये तो कालजयी बन जाएगी। एकाएक एक विस्फोट हो जाएगा, तहलका मच जाएगा ट्रेड यूनियन बिरादरी में। लेकिन लाभान्वित श्रमिक वर्ग होगा, इसमें संदेह नहीं है। एक बार फिर उक्त लेख के लिए साधुवाद। **- आशुतोष पाण्डेय, पूर्व महासचिव गुडईयर एम्पलॉयज यूनियन**